RAJYA SABHA

Monday, the 6th December 1993 15th Agrahayana, 1915 (Saka)

The House met at eleven of the clock, **The Deputy Chairman** in the Chair.

INTRODUCTION OF MINISTER

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI S. B. CHAVAN) : Madam Deputy Chairperson. I have the pleasure to introduce to you, and through you, to the House, my colleague, Shri Pranab Mukherjee, the Minister of Commerce.

ORAL ANSWER TO QUESTIONS

देश में कोयला उत्पादन

*41. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कोयला उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस समय किन-किन स्थानों पर कोयला खनन कार्य चल रहा है;

(ग) क्या सरकार ने कोयला खनन हेतु विदेशों के साथ कोई यांत्रिक करार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA) : (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

(a) Coal production in the country during last 3 years was as under :—

Statement

(Million tonnes)

	Coal production
1990-91 . .	211.73
1991-92 . .	229.28
1992-93 . . (Provisional)	238.33

(b) In India, main coal producing states are Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Orissa, Uttar Pradesh and West Bengal.

(c) and (d) Collaboration arrangements in the area of coal mining have been concluded with Australia, Canada, France, Germany, Poland, U. K. and erstwhile USSR with a view :

(i) to procure sophisticated high capacity equipments, including machinery for mining;

(ii) to acquire and asorb modern mining technology;

(iii) to train personnel in improved mining techniques and

(iv) to obtain concessional external assistance.

Following coal mining projects are presently under implementation with foreign assistance :

Country/ Organisation	Name of projects
Erstwhile USSR	1. Nigahi Opencast, NCL. 2. Khadia Opencast, NCL. 3. Jhanjra Underground, ECL.
France	1. Kottadih underground, ECL. 2. GDK-10 & 8 inclines, SCCL
Canada	1. Rajmahal Opencast ECL.
Australia	1. Piparwar Opencast, CCL.
Germany	1. Ramagundam II OCP, SCCL 2. Bina Deshaling Plant, NCL.
UK	1. GDK-11 A, SCCL. 2. GDK-9A Extn., SCCL. 3. GDK-10A, SCCL.
World Bank	1. Sonepur Bazari, OCP, ECL.

श्री शंकर दयाल सिंह : उपसभापति जी, हमारे सामने इस प्रश्न के उत्तर में जो जवाब आया है उससे एक बात की खुशी हो रही है कि 1990-91 से अधिक प्रोडक्शन 1991-92 में और 1991-92 से अधिक प्रोडक्शन 1992-93 में हुआ है

इसके लिए मैं कोल इंडिया को धन्यवाद और बधाई देता हूं। लेकिन मैं मुख्य रूप से जो सप्लीमेंटरी पूछना चाहता हूं वह अपने क्वेश्चन के (बी) और (सी), दो भागों के बारे में पूछना चाहता हूं। पहली बात मैं यह जानना चाहता हूं कि अपने बाहर से कोयला खनन क्षेत्रों में काम करने के लिए करार किए हैं और आपने ये करार आस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, पोलैण्ड, यू० के० और सोवियत संघ आदि से किये हैं। वहां से आप मशीनरी मंगवाते हैं, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि देश में इतने अधिक सार्वजनिक उपक्रम हैं जिनकी क्षमता बहुत बड़ी है और बगल में ही एच० ई० सी० जैसे बड़े सार्वजनिक उपक्रम हैं जो बीमार से चल रहे हैं, तो जो आप उन जगहों से खनन के लिए औजार या दूसरी तरह की मशीनरी मंगवाते हैं उनके बनाने की क्षमता अपने देश में है या नहीं? दूसरी बात मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इसके लिए आप कोई टेन्डर भी काल करते हैं या विदआउट टेन्डर खरीद होती है? अगर नहीं करते हैं तो देश में इसके लिए टेन्डर क्यों नहीं किया जाता है जिससे दूसरे सार्वजनिक उपक्रम भी इसमें हिस्सा ले सकें और ऐसी मशीनरी बना कर वे कोल इंडिया को दे सकें?

SHRI AJIT KUMAR PANJA : Madam, if the equipment are available and manufactured indigenously, indigenuos equipments are given first preference, taking into Consideration the time factor, utilisation and the quality of the machines. On a preliminary enquiry if we find that the public sector cannot give, then certainly we are to fall back on equipments manufactured outside India. There is another reason why we have to buy equipment from outside India, and it is bilateral agreements made with certain countries where we get easy credit; we also go in for buying certain equipment from outside the country. Taking into consideration the capacity which is required for certain very heavy machineries which are not manufactured in India or the time to be taken, the amount to be spent, the money that has been kept, and the production level to be reached for the purpose of meeting the energy demands of the country, we decide accordingly. Therefore, the gist is, (a) the indigenous equipmen. is given priority if it is available at the terms and condtions which are beneficial to coal production, and (b) we buy from outside if there is a good arrangement of foreign credit. So far as the tender is concerned, all most purchases are by tender, either by global tender or by tender within India.

श्री शंकर दयाल सिंह : मैडम, दूसरा मेरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि 13 ऐसी परियोजनाएं देश में हैं जिनके बारे में यह विवरण हमारे सामने है। विदेशी सहायता से ये परियोजनायें चल रही हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि ये जो 13 परियोजनायें हैं, जिनका नाम मैं यहां नहीं पढ़ रहा हूं, आपने अपने स्टेटमेंट में जिनका जिक्र किया है, उनमें किस परियोजना की अवधि कब तक के लिये है और कितने दिनों तक वे उन फारेन आफिसियल्स के साथ चलेंगी?

दूसरी बात यह है कि हमारी जानकारी के अनुसार बी०सी०सी०एल० और ई०सी०एल० दो आपके जो बड़े क्षेत्र हैं, वे अभी घाटे में चल रहे हैं? इनके लिये आपका कोलाबरेशन किन देशों के साथ है और उनसे घाटे में चलने का मुख्य कारण क्या है और इस घाटे को लाभ में बदला जा सके इसके लिए आप कौन सी कार्यवाही कर रहे हैं?

SHRI AJIT KUMAR PANJA : The names of the thirteen projects to which the hon. Member made a reference have not been given by the hon'ble member. I think the hon. Member is mentioning about the thirteen projects in which foreign collaborations have been obtained. The terms and conditions vary from project to project; according to the country involved in the project, the terms and conditions under which they want to give other assistance, whether it is a turnkey project or not, the amount of credit, the kind of collaboration and other things.

So far as the B. C. C. L. and E. C. L. are concerned, they are now running at a loss, but we expect that this year these two companies would make a turn-round

and start making profits. This loss has nothing to do with the foreign collaborations involved in the B. C. C. L. and E. C. L. These two companies are the oldest companies. Therefore, the old colliery process and the old method of working are still obtaining there. Gradually, it is being changed to modern concept.

श्री एस० एस० अहलुवालिया : महोदया, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में कोयले का उत्पादन अच्छा होने के बावजूद भी कहीं-कहीं पता लगता है कि हम कोयला इम्पोर्ट कर रहे हैं। मैंने इसके पहले कोयला विभाग से कई बार पत्राचार भी किया कि आपने कोयले का कैटेगराइजेशन कैसी-कैसी अवस्थाओं में किया है किस-किस भाग में किया है। आज तक कोयले के उत्पादन में हम लोगों ने कैटेगराइजेशन, स्टीम कोल, नॉन-स्टीम कोल या कोकोओवन कैटेगरी कोल पर ही करके रखा है। पर कुछ दिन पहले तक भी हमारे देश से कोयले का एक्सपोर्ट होता रहा है। जिस कोयले को वे बाहर ले जाते रहे हैं एक्चुअली वह सेमी-अन्थ्रासाइड कोल रहा है और उसका कैटेगराइजेशन नहीं नहीं हुआ। जापान यहां से इम्पोर्ट करके ले जाता रहा अर्थात् हम एक्सपोर्ट करते रहे और वही कोयला कैथोड बन कर, अन्थ्रासाइड में कैथोड बन कर हमारी एल्युमीनियम इंडस्ट्री में आता रहा। आपने जो अभी कोयले का इम्पोर्ट करने का प्रावधान रखा है, उसके लिये क्या कोई कंटिन्जेंसी प्लान है? क्या हमारे यहां का प्रोडक्शन, कोयला खदानें घाटे में जायेंगी? कौन सी क्वालिटी का कोयला ये इम्पोर्ट कर रहे हैं और क्या अभी भी कुछ कोयला आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कोयले के कैटेगराइजेशन के लिये आप क्या कदम उठा रहे हैं?

SHRI AJIT KUMAR PANJA : Madam, there are three parts in this question.

The first part is about the action plan which reduces our dependence on the imported coal. We have an action plan. A technical group was formed in the Ministry of Coal which found out the requirement of S. A. I. L., V. S. P. and T. I. S. C. O. It is estimated that this would increase from 16.36 million tonnes in 1992 to 22.79 million tonnes in 2002. As against this, indigenous availability can be increased from 11.35 million tonnes in 1992-93 to 20.71 million tonnes in 2002. Therefore, other things being same, the import would come down to about 2 million tonnes in 2002 compared to the present level of 6 million tonnes. This action plan has been made.

The salient features of this action plan are many. The important are : modernisation of the existing washeries to supply less ash-content coal, speedy commissioning of Madhuban and Kedla washeries, increased availability of coking coal in the country by augmenting the production of coking coal, construction of new washries and harnessing of new sources of coking coal. These are the main points.

श्री चतुरानन मिश्र : उपसभापति महोदया, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है कोल के इम्पोर्ट के बारे में उस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोल का प्राइस क्रैश कर गया है। उसमें घटती आ गई है 150 रुपये से ज्यादा पर टन की और इंडियन कोल जो है उसमें एश कन्टेंट ज्यादा है। इसलिए खतरा उपस्थित हो गया है कि पूरी कोल इंडस्ट्री बरबाद हो जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इससे अवगत है या नहीं है कि इंटरनेशनल प्राइस क्रैश कर गया है और इंडियन एश कन्टेंट आफ द कोल इज सो हाई। यह दूसरा है। इसी से संबंधित एक दूसरा है...

उपसभापति : एक का जवाब दे दें फिर आप दूसरा पूछ लीजिएगा।

श्री चतुरानन मिश्र : हमको तो एक ही चांस है।

उपसभापति : एक तो पूछ लीजिए। दूसरा पूछने जा रहे हैं। ए, बी, सी, डी, करेंगे तो दूसरे लोग नहीं पूछ पाएंगे।

श्री चतुरानन मिश्र : इसलिए तो हमने संबंधित कहा। बी, तो बोलने ही वाले थे तब तक आप बोल गयीं।

इससे संबंधित यह है कि मंत्री महोदय शायद वेल इन्फार्म्ड नहीं हैं या हाउस को इन्होंने मिसलीड किया है। वह यह मामला है कि इन्होंने कहा है कि हम टेंडर करते हैं विदेश से आने वाली मशीनरीज का। यह गलत बात है। इनको वे कर्जा देते हैं बैंक वाले कम इंटरेस्ट पर। हम इनको बताना चाहेंगे कि चीन वाले ने आपको 8 परसेंट इंटरेस्ट पर, कनाडा वालों ने 9 परसेंट इंटरेस्ट पर, इंग्लैंड वालों ने 9 से कुछ ज्यादा परसेंट पर इनको कर्जा दिया है और भारत का बैंक साढ़े 18 परसेंट इंटरेस्ट पर देता है। इसलिए ये सब अब विदेशम् शरणम् गच्छामि, यह करने के लिए जा रहे हैं। जो अब आप बोले हैं वह सही नहीं है और मैं सबूत में यह भी पेश करता हूं कि एच० ई० सी० में कोल इंडिया ने मशीन बनवा लिया है और अभी तक खरीदा नहीं है। वहां एक साल से पड़ा हुआ है। यह भी मैं आपको बता दूं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से इन दोनों मुद्दों पर सफाई चाहूंगा।

SHRI AJIT KUMAR PANJA : Whatever information I have given so far is correct to the hilt.

SHRI CHATURANAN MISHRA : You have not said anything about my first point, about international price crash.

SHRI AJIT KUMAR PANJA : The charge was that I did not give any correct information. I have given all the correct information so far.

SHRI DIGVIJAY SINGH: That was about part (b). What about the first Part?

SHRI AJIT KUMAR PANJA : If the first part is allowed I can say this that so far as the ash content of the coal is concerned, was are taking steps for beneficiation of coal and also for setting up washeries. Already Coal India has taken up five washeries. One will be completed next year and the rest will be coming up one by one in 1995 and 1996. But there is one benefit for Indian coal. It is environment friendly because of less sulphur content. This has to be highlighted. We are having a good market, we are trying to increase export of coal to Bangladesh and neighbouring countries first and then to other countries.

So far as indigenous consumption is concerned, even though there is crash in prices outside, we feel there would not be much import because of the cost involved in transporting coal from outside. Our indigenous coal is of good quality. What is necessary is several coal handling plants and more washeries to bring down the ash content so that it is useful to the consumers where it is required.

श्री चतुरानन मिश्र : मैडम, सिर्फ एक बात।

उपसभापति : अभी उनका आगे का क्वेश्चन तो जाने दीजिए।

श्री चतुरानन मिश्र : बैंक इंटरेस्ट रेट के बारे में उन्होंने कहा . . .

उपसभापति : उन्होंने कहा कि जो बोले हैं वह ठीक बोले हैं।

एक माननीय सदस्य : वे बोले ही नहीं हैं उसके बारे में . . .

श्रीमती रेणुका चौधरी : उन्होंने जवाब ही नहीं दिया तो ठीक कैसे बोले . . .

श्री चतुरानन मिश्र : वे जवाब तो दे दें . . . . **(व्यवधान)** . . . . हमने कहा कि विदेश वाले 8 परसेंट से 10 परसेंट इंटरेस्ट चार्ज पर देते हैं और इंडियन बैंक्स 18 परसेंट पर। इसलिए ये लोग विदेश की तरफ जा रहे हैं। इसका जवाब नहीं दिया है। मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं।

उपसभापति : अब फारेन बैंक से मालूम करके जवाब देंगे।

SHRI AJIT KUMAR PANJA : This is not correct.

SHRI CHATURANAN MISHRA : What is the correct rate of interest? At what rate have you taken loan किस रेट पर आपने लिया है यह बताइए।

SHRI AJIT KUMAR PANJA: Three supplementaries were asked in one question. I have answered two. About bank interest, the rate varies with the contracts entered into with foreign countries.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Ramdas Agarwal. (*Interruptions*). Please let us not make it into a Zero Hour. Let us treat it as a Question Hour.

श्री रामदास अग्रवाल : महोदया, कोल का प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ा यह संतोष की बात है। लेकिन मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि राजस्थान में लगभग 15 से 20 वर्ष पहले से लिगनाइट के डिपाजिट्स का बड़ा भंडार मिला था। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी तक वहां पर किसी प्रकार की परियोजना बनाने का भी आयोजन नहीं हुआ है।

उपसभापति : कोल से संबंधित सवाल पूछिए।

श्री रामदास अग्रवाल : महोदया, यह कोल से ही संबंधित है और महोदया, इन्होंने 13 परियोजनाएं दी हैं, लेकिन राजस्थान की कोई परियोजना अभी बनायी नहीं गयी है। यह मेरा मूल-प्रश्न होगा आखिर लिग्नाइट "बी" इतने बड़े डिपाजिट्स में है और इतने पिछड़े क्षेत्र में है जहां पर कि हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता था तो लिग्नाइट के प्रोडक्शन के लिए आपने कोई परियोजना बनाने का कष्ट क्यों नहीं किया? वहां पर नेवेली लिग्नाइट ने कांट्रेक्ट कर लिया था पिछले वर्ष, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसमें एक कदम भी आगे क्यों नहीं बढ़ाया, कृपया कर के इसका उत्तर दें?

SHRI AJIT KUMAR PANJA : Madam, this does not arise out of this question. However, as I know the answer to the hon. Member's question, I am answering it. Lignite has been found in Rajasthan. Now the question is whether the Government will run it from here in the same manner as the Neyveli Lignite Corporation in Tamil Nadu or give it to the Statement Government to start a company. This negotiation is going on. It appears that if we give it to the State Government to start a company with the expertise of the Neyveli Lignite Corporation, then it will be helpful. We have not yet finalized it.

*42. [*The Questioner* (*Shri Ghufran Azam*) *was absent. For answer vide col ... infra.*]

Distribution of Food articles through Public Distribution System

*43. **SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :**

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item published in "The Hindustan Times" dated, Ist September, 1993 under the caption 'PDS network in shambles';

(b) if so, whether it is a fact that there is delay in the distribution of rationed articles and their quality is also sub-standard; and

(c) what effective steps are being taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI A. K. ANTONY): (a) to (c) A Statement is being laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir. The news items is about the functioning of the Public Distribution System in the National Capital Territory (NCT) of Delhi.

(b) and (c) The operational responsibility for implementation of the Public Distribution System (PDS) is that of the State Governments and UT Administration.